



## बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की सफारिशें और बीआईटी मॉडल, 2015

### संदर्भ

भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने के लिये कौन से उपाय किये जाएँ और इन उपायों की रुपरेखा क्या हो? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिये न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए भारतीय मध्यस्थता कानून में कई बदलावों की सफारिश की है।

दरअसल, द्वपिक्षीय नविश संधि (bilateral investment treaty-BIT) पर इस समिति की सफारिशें इसलिये महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत वर्तमान में 20 बीआईटी विवादों से जूझ रहा है। इस समिति की अनुशंसाओं के बारे में जानने से पहले यह समझना होगा कि बीआईटी और इससे संबंधित विवाद क्या हैं।

### द्वपिक्षीय नविश संधियाँ (बीआईटी) क्या हैं?

- 1991 के आर्थिक संकट से पहले भारत द्वपिक्षीय नविश संधियों को महत्व इसलिये नहीं देता था, क्योंकि तब वह प्रत्यक्ष विदेशी नविश को गौण महत्त्व वाला समझता था। कर्नितु जैसे ही आर्थिक संकट ने भारत की जड़ें कमजोर करनी शुरू की, भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया।
- वतित्त प्रदायी इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत को करज देने के साथ ही उसे अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने को भी कहा। तत्पश्चात् भारत ने एलपीजी सुधारों की कवायद आरम्भ की और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत वभिन्न देशों के साथ द्वपिक्षीय नविश संधियाँ की।
- द्वपिक्षीय नविश संधियाँ महत्त्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से हैं कि इनकी अनुपस्थिति में कोई भी विदेशी नविशक, भारत द्वारा प्रतिकूल वनियामक दबाव बनाए जाने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिससे कि भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जा सके।
- ज़ाहिर है द्वपिक्षीय नविश संधि प्रत्यक्ष विदेशी नविश आकर्षित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

### क्यों है विवाद ?

- दरअसल, पछिले वर्ष भारत ने 58 देशों को सूचित कर दिया था कि वह उनके साथ अपनी द्वपिक्षीय नविश संधियों को नरिस्त करने जा रहा है।
- दरअसल, भारत बीआईटी के उस मॉडल का पालन करना चाहता है, जिसमें भारत की घरेलू नविश नीतियों को वैश्विक नविश परस्थितियों के अनुकूल बनाने की बात कही गई है।
- लेकिन इसके लिये सर्वप्रथम पहले की गई सन्धियों को नरिस्त करना था और फरि बीआईटी के नए मॉडल पर अन्य देशों को राजी करना था। नए मॉडल में व्यवस्था यह की गई थी कि कोई विदेशी नविशक किसी विवाद की स्थिति में मुआवज़े के लिये भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में आसानी से न घसीट पाए।
- नए मॉडल पर केवल उन्ही देशों के हस्ताक्षर करने की अधिक संभावना है जिनकी घरेलू परस्थितियाँ भारत जैसी ही हैं; यही कारण है कि आज बीआईटी के मुद्दे पर भारत लगभग 20 विवादों का सामना कर रहा है।

### क्यों गठित की गई बी.एन. श्रीकृष्ण समिति?

- अब जब भारत वर्ष 2015 के बीआईटी मॉडल के साथ कार्य करना चाहता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की सीमिति गुंजाइश है तो विवादों का नपिटारा भारतीय अदालतों में ही करना होगा।
- अतः नविश करने वाली संस्थाओं और देशों को यह विश्वास दलाना आवश्यक हो गया कि भारत के मध्यस्थता कानून व्यावहारिक और सक्षम हैं।
- भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का हब बनाने और वाणज्यिक विवादों के शीघ्र नपिटान हेतु रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह समिति गठित की गई।

### समिति की महत्त्वपूर्ण सफारिशें

- इस समिति ने सफारिश की है कि बीआईटी से संबंधित विवादों के जल्द नपिटान के लिये एक अन्तः मंत्रसितरीय समिति (inter-ministerial committee-IMC) का गठन किया जाए, जिसमें वतित्त, विदेश और कानून मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हों।
- समिति ने यह भी कहा है कि सरकार को कानूनी वशिषज्जता को बढ़ावा देने के लिये बाहर से बीआईटी मामलों के वशिषज्जों की सेवाएँ लेनी चाहिये।
- बटि विवादों से लड़ने के लिये एक वशिष नधिा का नरिमाण करना चाहिये।

- भारत के बीआईटी दायित्वों एवं उनके नहितारथ को बेहतर ढंग से समझने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों की क्षमता बढ़ानी चाहिये।
- इस समिति की सबसे महत्त्वपूर्ण सफिरशि अंतरराष्ट्रीय कानूनी वविादों पर सरकार को सलाह देने के लिये एक 'अंतरराष्ट्रीय कानून सलाहकार' (international law adviser-ILA)) पद के गठन की सफिरशि करना है।
- कहा गया है कि यह 'अंतरराष्ट्रीय कानून सलाहकार' ही बीआईटी मध्यस्थता के दनि-प्रतदिनि के प्रबंधन के लिये ज़मिमेदार होगा।
- बीआईटी वविादों के समाधान के लिये समिति ने कुछ उपयोगी हस्तकषप किए हैं, जैसे कि बीआईटी अपीलीय तंत्र और एक बहुपक्षीय नविश अदालत की स्थापना की चर्चा करना।

### इन सफिरशियों को कैसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता था ?

- समितिकी सबसे महत्त्वपूर्ण सफिरशि को लेकर ही कुछ चिंताएँ सामने आ रही हैं। समिति ने बीआईटी वविादों को देखने के लिये एक विशेषज्ञ पद के गठन की बात की है, जिसे 'अंतरराष्ट्रीय कानून सलाहकार' के नाम से जाना जाएगा।
- दरअसल, वदिश मंत्रालय का एक वभिग, जिसे हम 'द लीगल एंड ट्रीटीज़' (The Legal and Treaties-L&T) के नाम से जानते हैं का यह दायित्व है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनी मामलों में सरकार को आवश्यक सुझाव दे।
- जब पहले से ही इस कार्य के लिये एक वभिग है तो एक नए पद का निर्माण इन मामलों में दायित्वों के दोहराव की स्थिति ला सकता है। ज़रूरी यह था कि 'द लीगल एंड ट्रीटीज़' वभिग को ही और अधिक मज़बूत बनाया जाए।
- दूसरा वविाद भारत ने नए बीआईटी मॉडल के अनुच्छेद 15 से संबंधित है। वदिति हो कि इस समिति ने इस अनुच्छेद की प्रशंसा की है, जबकि इसमें खामियाँ हैं।
- बीआईटी मॉडल, 2015 के अनुच्छेद 15 के अनुसार वविाद की स्थिति में वदिशी नविशकों को कम से कम पाँच साल की अवधि के लिये घरेलू अदालतों में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है। इसके बाद ही नविशक बीआईटी के तहत वविाद नपिटारे का आग्रह कर सकते हैं।
- हालाँकि इस आग्रह के बाद उन्हें 6 माह तक शांतपूरवक समाधान निकालने की कोशिश करनी होगी। यदतिब भी कोई नषिकर्ष नहीं निकलता तो नविशकों को बीआईटी के तहत वविाद नपिटारे के लिये 3 माह का समय दिया जाता है।
- इस तरह के बाध्यकारी प्रावधानों के संबंध में समिति कुछ सुधारात्मक सुझाव दे सकती थी, लेकिन उसने इस व्यवस्था को उचित बताया है।

### नषिकर्ष

- वदिति हो कि वर्ष 1993 में भारत ने बीआईटी का अपना पहला मॉडल तैयार किया था, लेकिन तब और आज की परस्थितियों में नाटकीय बदलाव आया है।
- हालाँकि वर्ष 2003 में बीआईटी मॉडल में कुछ बदलाव किया गया, लेकिन बदलती हुई आर्थिक स्थितियों के कारण उसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता थी और यही कारण है कि हमने 2015 का मॉडल अपनाया।
- बीआईटी के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नकियों ने प्रायः भारत के वरिद्ध पक्षपाती नरिणय दिये हैं। यही कारण है कि नए मॉडल ने नविशकों के लिये अंतरराष्ट्रीय पंचाट तक पहुँचना मुश्किल बना दिया।
- बी.एन. शरीकृषण समिति के पास मौका था कि वह थोड़ा प्रतकिरियावादी नज़र आ रहे इस मॉडल को लेकर कुछ व्यावहारिक सुझाव दे।
- हालाँकि, केवल बीआईटी ही नविश आकर्षित करने का साधन नहीं है, बलककििसी अर्थव्यवस्था की वृद्धिदर कैसी है, भूमि तथा श्रम की उपलब्धता कैसी है आदि कुछ ऐसे घटक हैं जो प्रत्यक्ष वदिशी नविश आकर्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं।